बड़ी अजीब सी है दुनिया, यहां लोग मिलते कम है, झॉकते ज्यादा है।
– अज्ञात

अच्छी–खासी गिरावट दर्ज

वैसे तो रिपोर्ट में भी यह बात आई है कि भारत के शहरों के कमजोर प्रदर्शन का मुख्य कारण यह है कि वे महामारी के लिए तैयार नहीं थे, मगर इस तथ्य का सबसे स्पष्ट प्रदर्शन शहरों से गांवों की ओर हुए अभूतपूर्व पलायन में हुआ।

मनोज झा।।

इंस्टिट्यूट फॉर मैनेजमेंट डिवेलपमेंट (स्विट्जरलैंड) ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नॉलजी एंड डिजाइन के साथ मिलकर 2020 का जो स्मार्ट सिटी इंडेक्स (एससीआई) जारी किया है, उसमें भारत के चार शहर शामिल हैं। और खास बात यह कि चारों की रैंकिंग में पिछले साल के मुकाबले अच्छी–खासी गिरावट दर्ज हुई है। इसके कारणों पर जाने से पहले यह जानना जरूरी है कि एससीआई–2020 इस मायने में भी विशिष्ट है कि इसे वैश्विक महामारी कोरोना के कहर के दौरान ही तैयार किया गया है। दुनिया भर के 109 शहरों में से हर शहर के 120 निवासियों से इस रिपोर्ट के लिए बातचीत अप्रैल और मई के महीनों में की गई जब लोग कोरोना के आतंक के साये में थे और ज्यादातर शहर लॉकडाउन से गुजर रहे थे।

स्वाभाविक रूप से इस इस रिपोर्ट में यह बात भी दर्ज हुई है कि अलग–अलग शहरों और वहां के निवासियों के नजरिये पर इस महामारी ने किस तरह का प्रभाव डाला है। वैसे इस इंडेक्स के संदर्भ में स्मार्ट सिटी का मतलब ऐसे शहरों से है जहां टेक्नॉलजी का इस्तेमाल शहरीकरण के फायदों को बढ़ाने और इसके नुकसानों को कम करने में होता हो। इसमें रैंकिंग तय करने के लिए आर्थिक और तकनीकी आंकड़े तो लिए ही जाते हैं, लेकिन खास जोर इस बात पर होता है कि शहर में रहने वाले नागरिक उसको कितना स्मार्ट मानते हैं। सो इन कसौटियों पर अपने देश के चारों शहर पहले से बदतर पाए गए। हैदराबाद 67वें से 85वें, नई दिल्ली 68वें से 86वें, मुंबई 78वें से 93वें और बेंगलुरु 79वें से 95वें नंबर पर आ गया। अन्य बातों के अलावा इसका एक सीधा मतलब यह भी है कि कोरोना के दौर में हमारे देश के शहरों में रह रहे लोगों का भरोसा खास तौर पर हिल गया था।

वैसे तो रिपोर्ट में भी यह बात आई है कि भारत के शहरों के कमजोर प्रदर्शन का मुख्य कारण यह है कि वे महामारी के लिए तैयार नहीं थे, मगर इस तथ्य का सबसे स्पष्ट प्रदर्शन शहरों से गांवों की ओर हुए अभूतपूर्व पलायन में हुआ। लॉकडाउन लागू होने के बाद छोटे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के साथ पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पर निकल पड़े लोगों की मनःस्थिति से बेहतर इसका सूचकांक भला और क्या हो सकता है। इससे यह सचाई खुलकर सामने आ गई कि गांवों से नाउम्मीद होकर शहरों में अपना जीवन खपा रहे लोगों के भीतर कोई भरोसा हमारे शहर नहीं जगा पाए हैं। एक ऐसे दौर में, जब कृषि का योगदान जीडीपी में लगातार कम होता जा रहा है और अभी की अपवाद स्थितियों को छोड़ दिया जाए तो इसे कम ही होते जाना है, शहरों की साख पर लगा यह बट्टा एक राष्ट्र के रूप में हमारे लिए भारी पड़ने वाला है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स की कसौटियां अपनी जगह हैं, लेकिन हमारे शहरों को खुद पर लगा यह दाग धोने के लिए काफी मशक्कत करनी होगी।

कला से प्रेम करो

अशोक वोहरा।

धर्म-दर्शन

संगीत व कलाओं का हमारे जीवन में विशिष्ट स्थान है। भगवान ने मोरपंख व बांसुरी धारण करके कला, संस्कृति व पर्यावरण के प्रति अपने लगाव को दर्शाया।

इनके जरिए उन्होंने संदेश दिया कि जीवन को सुंदर बनाने में संगीत व कला का भी महत्वपूर्ण योगदान है।

कमजोर व निर्बल का सहारा बनो। निर्धन बाल सखा सुदामा हो या षड्यंत्र का शिकार पांडव, श्रीकृष्ण ने सदा निर्बलों का साथ दिया और उन्हें मुसीबत से उबारा।

अन्याय का प्रतिकार करो रू अन्याय का सदा विरोध होना चाहिए। श्रीकृष्ण की शांतिप्रियता कायर की नहीं बल्कि एक वीर की थी। उन्होंने अन्याय कभी स्वीकार नहीं किया। शांतिप्रिय होने के बावजूद शत्रु अगर गलत है तो उसके शमन में पीछे नहीं हटें।

संपादकीय

जोखिम से बचाव

प्रधानमंत्री द्वारा बिहार में विकास कार्यों का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री की इसके लिए सराहना की गई है कि किस प्रकार 14 वर्ष पूर्व वहां मंडी व्यवस्था समाप्त की जा चुकी है। वहां मंडी का स्थान सड़क किनारे लगने वाले थोक बाजार ले चुके हैं। संसद के दोनों सदनों में जनता दल (यू) ने विधेयकों का समर्थन किया है। रबी की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर प्रधानमंत्री ने पहल की है कि मंडी और बाहर दोनों ठिकानों पर किसान अपनी उपज बेच सकेंगे। लेकिन समर्थन मूल्य की गारंटी को कानूनी जामा पहनाया जाना लाजिमी है। इसी तरह अनुबंध खेती के विस्तार से पूर्व सभी कारकों पर ठीक से विचार करने की आवश्यकता है। यह मॉडल कई चूकों और खतरों से भरा पड़ा है। यह सौदा दो बेहद असमान साझेदारों के बीच किया जाता है। इनमें एक तरफ किसान होता है तो दूसरी तरफ कॉरपोरेट वर्ग, जिसकी नीति निर्धारकों के यहां अच्छी पहुंच है। कीटनाशक, उर्वरक और खेती में काम आने वाले उपकरणों को या तो उसी की कंपनी के द्वारा निर्मित किया जाता है या उसके सहयोगी निर्माता द्वारा तैयार किया जाता है। तीसरे, विधेयक के सरकारी पक्ष के अनुसार इस समय कृषि वस्तुओं का अत्यधिक उत्पादन हो रहा है। आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट के मुताबिक कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, प्रॉसेसिंग और एक्सपोर्ट में निवेश कम होने की वजह से किसानों को लाभ नहीं हो पाता है। इसके अलावा गैर सरकारी खरीद कभी किसी बड़े जोखिम को जन्म न दे, इसके लिए भी खरीद की सरकारी व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता है।

मोदी ने भारत की वैविध्यपूर्ण संस्कृति के लिए बार-बार अपना समर्थन दिखाया है, चाहे वह नृत्य, कला, संगीत, पोशाक और खान-पान की आदत आदि जिस भी रूप में हो। वे सही मायनों में इसके सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक राजदूत रहे हैं।

चौतरफा विरोध

केसी त्यागी

बीते 5 जून को सरकार की ओर से जारी कृषि संबंधी तीनों अध्यादेशों को संसद द्वारा कानून का रूप दिया जा चुका है। अकाली दल और जेजेपी पंजाब और हरियाणा में एनडीए के प्रमुख सहयोगी दल हैं। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के सक्रिय सहयोग के कारण ही खट्टरसरकार अस्तित्व में आई है। इसके कई पदाधिकारी तीनों अध्यादेशों के खिलाफ सड़क पर चल रहे संघर्षों में अन्य किसान संगठनों के साथ दिख रहे हैं। उधर पंजाब में अकाली दल के लोग किसान संगठनों के साथ धरना और प्रदर्शनों में बराबर हिस्सेदारी कर रहे हैं। असल में किसान आंदोलन अकाली राजनीति का हिस्सा रहे हैं। पंजाब देश का अकेला प्रांत है, जो शत–प्रतिशत सिंचित है और देश की गेहूं व चावल की बड़ी जरूरत पूरी करता है। जन खाद्य वितरण प्रणाली में एफसीआई के जरिए बड़ी हिस्सेदारी यहीं से आती है। यहां की खन्ना अनाज मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है।

स्वाभाविक ही, मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह तीनों विधेयकों के विरोध में काफी सक्रिय हैं। उन्होंने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर तीनों विधेयकों को निरस्त करा दिया और इस प्रकार

गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान के कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी इन विधेयकों का विरोध कर चुके हैं। कांग्रेस के तमाम मुख्यमंत्री इसे संघवाद की भावना के विरुद्ध बता रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार उनसे बातचीत किए बगैर ये बिल उनके सिर पर थोप रही है। देशभर के लगभग 200 किसान संगठनों के प्रतिनिधि राजधानी दिल्ली स्थित जंतर–मंतर पर विरोध स्वरूप धरना दिए बैठे हैं। लोकसभा में विधेयकों पर चर्चा के दौरान अकाली दल प्रमुख और सांसद सुखबीर बादल ने न सिर्फ विधेयक का विरोध किया, बल्कि एक कदम आगे बढ़ सहयोगी पार्टी बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। उनका यह आरोप काफी गंभीर है कि बिल से जुड़ा अध्यादेश कैबिनेट में लाने से पहले सहयोगी दलों को भरोसे में नहीं लिया गया। इसी तरह जम्मू–कश्मीर राज्य से धारा 370 और एनआरसी के मुद्दे पर व्यापक विचार विमर्श के अभाव में जेडी(यू) का भी साथ बीजेपी सदन में प्राप्त नहीं कर पाई थी। सुखबीर बादल के अनुसार यह बिल किसानों, मंडियों, आढ़तियों और खेत मजदूरों के हितों के विरुद्ध है। 17 सितंबर को बहस के दौरान संसद का राजनीतिक तापमान बढ़ गया, जब अकाली दल की एकमात्र मंत्री हरसिमत कौर ने मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देकर इस मसले को गंभीर बना दिया। अकाली दल 30–35 वर्षों से जनसंघ और बीजेपी की विश्वस्त सहयोगी पार्टी रही है। सरदार प्रकाश सिंह बादल के प्रति सम्मान से प्रधानमंत्री इतने ओतप्रोत रहते हैं कि कई अवसरों पर सार्वजनिक रूप से उनके चरण स्पर्श करते दिखाई दिए हैं। लेकिन कृषि मंत्री के तर्क अकाली नेतृत्व को संतुष्ट नहीं कर पाए।

बीते गुरुवार की शाम प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट के जरिए आश्वासन दिया कि एमएसपी की प्रक्रिया जारी रहेगी और वितरण प्रणाली में कोई बदलाव नहीं होगा। यह सही है कि किसानों के पास अपनी फसल बेचने के ज्यादा विकल्प नहीं हैं। उनको अपनी फसल कृषि उपज विपणन समितियों में बेचनी होती है। नए कानून से वे मनचाहे स्थान पर फसल बेच सकेंगे। लेकिन किसान संगठनों का मानना है कि कृषि उपज मंडियों से किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिलता रहा है।

सूडोकु नवताल-5482

सरल

7	8	6		1		5		2
	9			8				3
1			6	9		7		
	3	8	2		1			
2	7	5				6	3	1
			5		7	2	8	
		9		7	4			6
8				2			5	
4		2		5		9	1	7

Jagrutidaur.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5481 का हल

2	9	5	3	1	4	6	8	7
3	6	1	2	8	7	4	9	5
8	4	7	5	9	6	3	2	1
5	7	4	1	6	2	8	3	9
1	3	6	9	4	8	5	7	2
9	8	2	7	3	5	1	4	6
6	2	8	4	7	1	9	5	3
4	5	3	6	2	9	7	1	8
7	1	9	8	5	3	2	6	4

अपना ब्लॉग

स्वामीनाथन फॉर्म्युले के आधार पर हो

मोहन। नए विधेयक के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी मान्यता प्रदान कर इसे और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। हालांकि मूल्य निर्धारण स्वामीनाथन फॉर्म्युले के आधार पर होना चाहिए। रबी और खरीफ की फसल का बंपर उत्पादन होने के बावजूद मात्र 3 से 5 प्रतिशत तक फसलों और दालों के दामों में वृद्धि हो पाई है। इस एक्ट के बाद उत्पादन, स्टोरेज, मूवमेंट और वितरण पर सरकारी नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। कारोबारी फसल सीजन में जमाखोरी करेंगे, कीमतों में अस्थिरता आएगी और खाद्य सुरक्षा पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। वरिष्ठ बीजेपी नेता शांता कुमार की अध्यक्षता में गठित समिति पहले ही निजी प्रतिष्ठानों को अनाज के क्रय और भंडारण की अनुमति की अनुशंसा कर चुकी है। प्रधानमंत्री राहत योजना के तहत जिस प्रकार कोरोना काल में करोड़ो लोगों को मुफ्त राशन वितरण किया गया है, क्या उस दौर में यह संभव होगा?